तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण नीति पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं : टीकाराम जूली

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति का मुद्दा गर्माया रहा।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा सरकार को चुनावी वादों की याद दिलाते हुए जमकर घेरा। जब शिक्षा मंत्री ने तबादलों के प्रावधान पर भ्रम की स्थिति पैदा की, तो जूली ने उन्हें सीधे सवालों के कटघरे में खडा कर दिया।

सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधे तौर पर पूछा कि सरकार का आधा समय बीत चुका है और सवा 2 साल से अधिक का वक्त हो जाने के बावजूद तबादला नीति अब तक क्यों नहीं बनी? उन्होंने सरकार से पूछा, ''क्या आप कोई टाइम-लाइन देना चाहेंगे कि आखिर कब इनके ट्रांसफर होंगे?''।

जूली ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के लाखों शिक्षकों को गुमराह कर रही है, जबकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नीति बनाने का वादा किया था। सदन में जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछली सरकारों के आंकड़ों और भाजपा के समय हुए 2200 तबादलों का हवाला दिया, तो नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ''कांग्रेस ने किए या भाजपा ने किए, उन पुरानी बातों को छोड़ें''। जूली ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि वर्तमान सरकार अपनी घोषणा के अनुसार नीति कब तक बनाएगी।

भजनलाल सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए बजट में 32526 करोड़ रु. का प्रावधान किया

यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है, जो कि सरकार का लक्ष्य 'निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान' के लिए अहम है

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए बजट 2026-27 में 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि वर्ष 2023-24 की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है। सरकार का लक्ष्य 'निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान' है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान डिजिटल हैल्थ मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 6.52 करोड़ आभा आईडी जारी की जा चुकी हैं। इससे मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप से उपलब्ध हो रही है। वहीं ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन के जरिए 20.33 लाख मरीजों को घर बैठे परामर्श मिला। सरकार आरजीएचएस, आयुष्मान वय वंदन योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाओं से हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही है। बच्चों के बेहतर इलाज के लिए जयपुर स्थित जे.के. लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का नया आईपीडी टॉवर बनेगा। यहां पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग भी स्थापित होगा।

इसके साथ ही आरयूएचएस अस्पताल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी और निओनेटल आईसीयू विकसित किया जाएगा।

जयपुर मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के अन्य प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को भी बजट में मजबूत किया गया है।

इसमें जोधपुर के लिए 461 करोड़, उदयपुर के लिए 333 करोड़, कोटा के लिए 341 करोड़, अजमेर के लिए 345 करोड़ और बीकानेर के लिए 276 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इन संस्थानों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, ट्रॉमा सर्जरी सुपर स्पेशलिटी कोर्स और बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे।

राज्य में वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2,875 पीएचसी, 15,292 उप स्वास्थ्य केंद्र और 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं।

बजट में कई पीएचसी को सीएचसी, सीएचसी को उप जिला अस्पताल और उप स्वास्थ्य केंद्रों को आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नत किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में त्वरित उपचार के लिए 'राज सुरक्षा' योजना लागू की जाएगी। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे के लिए क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर स्थापित होगा। हाईवे पर एंबुलेंस तैनात की जाएंगी। ट्रॉमा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं। साथ ही 'मोक्ष वाहिनी' योजना के तहत दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 2,179 हेल्थ पैकेज में 25 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा है। 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं और 2025-26 में 15 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। अब असहाय, विमंदित और लावारिस रोगियों को भी मुफ्त इलाज मिलेगा।

पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए 'राज ममता प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ' स्थापित होगा। जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल और अस्पतालों में मनोचिकित्सक व काउंसलर उपलब्ध कराए जाएंगे।

पिता ने आठ माह की बेटी की कैंची से गला रेतकर हत्या की

आरोपी सादाब ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया

जयपुर (कासं)। मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बाद एक पिता ने अपनी आठ माह की मासूम बेटी की कैंची से गला काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपित पिता से पूछताछ में जुटी है।

थानाधिकारी उदयभान यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बहराइच निवासी सादाब (19) को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी शादी जुलाई 2025 में मालपुरा गेट स्थित अंबेडकर कॉलोनी निवासी रूकसार बानो (19) से हुई थी। दंपती की आठ माह की बेटी सहनाज थी।

करीब छह दिन पहले सादाब पत्नी और बेटी को लेकर ससुराल अंबेडकर कॉलोनी आया था। 6 फरवरी सुबह करीब 10 बजे गांव वापस लौटने की बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। पत्नी द्वारा कुछ दिन और रुकने की बात कहने पर सादाब ने मारपीट की और उसका गला दबाने का प्रयास किया। इस दौरान साले सोहिल ने बीच-बचाव किया। जिससे आरोपी और भड़क गया। बताया गया कि सादाब ने सोहिल के सिर पर स्टील की केतली से वार किया। शोर-शराबा सुनकर पडौसी मौके पर पहुंचे और दोनों को छुडाया। इसी बीच आरोपी ने बेटी सहनाज को सोहिल की गोद से छीन लिया और कमरे में बंद हो गया।

कमरे के भीतर सादाब ने कैंची से बच्ची का गला काट दिया और शव को कंबल में छिपा दिया। इसके बाद उसने फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

विधायक रोहित बोहरा द्वारा सदन में अश्लील इशारा करने का मुद्दा गर्माया

सत्ता पक्ष ने इस आचरण को सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग उठाई, जबकि विपक्ष ने सहानुभूति बरतने का आग्रह

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा द्वारा कथित अश्लील इशारा करने का मामला शुक्रवार को सदन में गर्माया। पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने शुक्रवार को सदन में यह मुद्दा उठाते हुए विधायक के आचरण पर खड़े किए और कार्रवाई की मांग की। सत्ता पक्ष के मंत्री व विधायकों ने रोहित बोहरा के इस आचरण को सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की, जबकि विपक्ष ने सहानुभूति बरतने का आग्रह किया।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वे संबंधित वीडियो फुटेज देखेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आचरण सदन की गरिमा के प्रतिकूल पाया गया तो नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को सदन में यह मुद्दा भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने सदन के भीतर अश्लील इशारा किया, जो विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। कृपलानी ने अध्यक्ष से व्यवस्था देने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा की समृद्ध परंपराएं रही हैं, लेकिन हाल के समय में आचरण का स्तर गिरता दिखाई दे रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि आचरण और वाणी से जुड़े विषय अत्यंत संवेदनशील होते हैं। बहस के दौरान सदस्य कभी-कभी उत्तेजित हो सकते हैं, लेकिन सदन के भीतर और बाहर मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक शांति धारीवाल पहले भी अभद्र भाषा का उपयोग कर चुके हैं, और अब अश्लील इशारे जैसी घटना अत्यंत चिंताजनक है।

- **विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वे संबंधित वीडियो फुटेज देखेंगे। यदि आचरण सदन की गरिमा के प्रतिकूल पाया गया तो नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।**

विपक्ष के सचेतक ने कहा कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं पर सदन में माफी दी गई है। उन्होंने आग्रह किया कि रोहित बोहरा के मामले में भी सहानुभूति रखते हुए माफी देकर प्रकरण को समाप्त किया जाए।

अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता सदन की कार्यवाही देखती है और हर विधायक लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों से मर्यादित और जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। गुरुवार को शून्यकाल के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया था। जब कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा सरकारी कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान उनके पीछे बैठे रोहित बोहरा पहले किसी विधायक की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे, लेकिन कुछ क्षण बाद कैमरे में हंसते हुए कथित रूप से अभद्र इशारा करते नजर आए। यह दृश्य विधानसभा की लाइव फीड में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई।

'ब्लास्टिंग से चित्तौडगढ़ किले में दरारें पड़ रही'

जयपुर। विधानसभा में बजट बहस के दौरान शुक्रवार को भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि उद्योगों की ब्लास्टिंग के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दरारें पड़ रही है। राजस्थान अपनी संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली परंपराओं के कारण जाना जाता है।

हर शहर की अपनी पहचान होती है, उस पहचान को कायम रखना होगा। विश्वराज सिंह ने कहा कि अरावली को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे।

अवैध खनन पर रोक लगानी होगी। नाथद्वारा में अनेक मगरे काटे जा रहे हैं, अवैध खान की जांच होनी चाहिए। हमें पर्यावरण को लेकर सोच बदलनी होगी। पर्यावरण हमें संभालता है।

ओपीजेएस यूनिवर्सिटी बंद, 10 निजी विश्वविद्यालयों की जांच शुरू : बैरवा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में फर्जी डिग्री कांड पर राज्य सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। फर्जीवाडे की गंभीर आरोपों के कारण चूरू जिले की ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी को बंद करते हुए 10 निजी विश्वविद्यालयों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने यह जानकारी शुक्रवार को भाजपा विधायक कालीचरण सराफ के प्रश्न के जवाब में दी।

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि फर्जीवाडे के गंभीर आरोपों के बाद 7 जनवरी को ओपीजेएस विश्वविद्यालय का परिसमापन कर दिया है। यहां के प्रशासन की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त बीकानेर को सौंपी गई है। मामले में कई दोषी कार्मिकों और दलालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी तरह मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी फर्जी डिग्री प्रकरण में दोषी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विश्वविद्यालयों की जांच अभी जारी है।

डॉ. बैरवा ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 10 विश्वविद्यालयों के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें मिलने पर जांच शुरू की गई है।

जांच के दायरे में शामिल प्रमुख संस्थानों में सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनूं, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर, श्रीधर विश्वविद्यालय झुंझुनूं, माधव विश्वविद्यालय सिरोही, रैफल्स विश्वविद्यालय अलवर, निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर और जगदीश झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय झुंझुनूं शामिल है।

शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 में अनियमितताओं के आरोपों के बाद कुछ विश्वविद्यालयों की समग्र जांच एसओजी को सौंपी गई है। पुलिस जांच में बैक डेट में डिग्रियां और अंकतालिकाएं जारी करने की शिकायतें सामने आईं। इस संबंध में ओपीजेएस विश्वविद्यालय के संचालक जोगेंद्र सिंह समेत कई पूर्व अधिकारी और कथित दलाल गिरफ्तार किए जा चुके है। मेवाड़ विश्वविद्यालय के भी कुछ अधिकारियों को जेल भेजा गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियामक आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले तैयार किए गए 'राजस्थान प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल-2023' के प्रावधानों को और मजबूत बनाने के लिए नई समिति गठित की गई है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। नया प्रारूप जल्द विधि विभाग को भेजा जाएगा।

- **उपमुख्यमंत्री ने सदन में कहा ''फर्जी डिग्री कांड पर राज्य सरकार ने लिया सख्त एक्शन''**
- **मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी फर्जी डिग्री प्रकरण में दोषी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है : बैरवा**
- **उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियामक आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है।**

राजस्थान विधानसभा में चोर-डाकू की टिप्पणियों से काफी हंगामा मचा

बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने भाजपा को कांग्रेस के नेता चुराने वाला बताया तो सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने भी कांग्रेस को ''डाकू'' कह दिया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस-भाजपा विधायकों ने एक-दूसरे की पार्टियों को चोर और डाकू बताकर टिप्पणियां की तो सदन में हंगामा मच गया।

शुक्रवार को बजट पर बहस के दौरान विधायक हरिमोहन शर्मा ने भाजपा को कांग्रेस के नेता चुराने वाला बताया तो सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को डाकू बता दिया। दोनों विधायकों की इन टिप्पणियों से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर बाधित रही। हालांकि बाद में आसन में दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत करवाया।

- **दोनों विधायकों की इन टिप्पणियों से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोंकझोंक हुई, हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर बाधित रही**
- **गोपाल शर्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ''मेरे पास कांग्रेस राज के 8 लाख करोड़ के घोटाले का ब्यौरा है, इसे मैं साथ लेकर आया हूं। एक पूर्व मंत्री को जेल भेज दिया तो दूसरे पूर्व मंत्री को क्यों छोड़ दिया? वो छाती ठोक ठोककर कहते हैं हिम्मत है तो जेल भेजो।''**

दरअसल शुक्रवार को बजट पर बहस के दौरान सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि ''राजस्थान को गाडगिल फॉर्मूले में लाने वाले प्रणब मुखर्जी थे, जिनकी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आपने निंदा की थी।'' गोपाल शर्मा की चर्चा के दौरान बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने खडत्रे हो गए और उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि ''आप कांग्रेस-नेता चोर हो, मतलब कांग्रेस के नेताओं को ही चुरा लेते हो।''

इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि, ''यह रिकॉर्ड में जाना चाहिए, आप कह रहे हो कांग्रेस नेता चोर है।'' जिस पर गोपाल शर्मा ने कहा कि ''कांग्रेस नेता चोर नहीं, डाकू है।'' गोपाल शर्मा की इस टिप्पणी से सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणियां करते हुए नोंकझोंक शुरू कर दी। इसी बीच गोपाल शर्मा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ''मेरे पास कांग्रेस राज के 8 लाख करोड़ के घोटाले का ब्यौरा है, इसे मैं साथ लेकर आया हूं। एक पूर्व मंत्री को जेल भेज दिया तो दूसरे पूर्व मंत्री को क्यों छोड़ दिया? वो छाती ठोक ठोककर कहते हैं हिम्मत है तो जेल भेजो।''

इस पूरे घटनाक्रम और बयानबाजी के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर तक बाधित रही। बाद में आसन ने दोनों पक्षों से समझाइश करते हुए मामला शांत कराया। देर शाम सदन की कार्यवाही 16 फरवरी को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

रैपिडो बाइक चालक ने युवती से की छेड़छाड़

जयपुर। एक युवती को अकेले में रैपिडो कैब बुक करना भारी पड़ गया। शातिर रैपिडो चालक युवती को गलत जगह ले जाने लगा। इस पर पर युवती ने विरोध किया तो रैपिडो चालक ने उसे धमकी दी। इसी दौरान रैपिडो पर बैठी युवती को थोड़ा आगे जाकर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई तो युवती ने मदद के लिए शोर मचा दिया। लोगों को इकट्ठा होते देख रैपिडो चालक युवती को उतार कर फरार हो गया। जिसके बाद युवती ने मामले की जानकारी भांकरोटा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय युवती का आरोप है कि गुरुवार को उसने घर जाने के लिए रैपिडो बुक की थी। रैपिडो चालक उसे बाइक पर बैठाकर गलत रास्ते में ले गया। विरोध करने पर आरोपी रैपिडो चालक ने उसे धमकी दी। सुनसान जगह ले जाने लगा। तभी युवती को एक कंपनी के कुछ लोग खड़े दिखाई दिए।

'बी.सी.आर. कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी एजी की कमेटी क्यों गठित नहीं?'

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान और महाधिवक्ता से पूछा है कि बीसीआर की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित क्यों नहीं की गई है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 17 जुलाई, 2023 को पूरा हो गया था। इससे पूर्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर 15 मई को इस कार्यकाल को छह माह के लिए बढा दिया। याचिका में कहा गया कि इस दौरान बीसीआई ने एडवोकेट्स प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम में संशोधन कर वकीलों के प्रैक्टिस प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम पूरा होने तक 26 जून, 2023 के गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस कार्यकाल को डेढ साल के लिए फिर से बढा दिया। याचिका में कहा गया कि यह बढा हुआ कार्यकाल भी दिसंबर, 2024 में पूरा हो चुका है। ऐसे में एडवोकेट एक्ट की धारा 8ए के तहत महाधिवक्ता की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जानी चाहिए थी। इसे लेकर याचिकाकर्ता की ओर से बीसीआर को लीगल नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कौंसिल की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर नोकझोंक हुई

जयपुर (विसं)। विधानसभा में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर मंत्री कन्हैयालाल और विपक्ष के बीच नोकझोंक हो गई। भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा के सवाल के जवाब में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल जीवन मिशन की गड़बड़ियों पर कार्रवाई का जिक्र किया।

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक सवाल करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर केवल छोटे लेवल पर ही कार्रवाई की है। आपने दावा किया कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आपने केवल जेईएन-एईएन ही सस्पेंड किए है या किसी आईएएस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की है? कौन सीनियर अधिकारी थे, जिनके साइन से टैंडर हुए। उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं या नहीं?

मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि जल जीवन मिशन में जो भी दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व जलदाय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी जो अधिकारी हैं, तत्कालीन एसीएस हैं, उनके खिलाफ भी हमने एसीबी में मुकदमा दर्ज करवाया है। जो कोई दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अफसर का नाम बताइए। केवल गोलमाल किया जा रहा है, नाम बताइए। इसी बीच स्पीकर ने कहा कि नाम थोड़े ही बताया जाता है।

सदन में सवालों के जवाब देने में चूके उपमुख्यमंत्री बैरवा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा एक सवाल का जवाब देने के दौरान गलती कर गए। बैरवा भाजपा विधायक कल्पना देवी के लाडपुरा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा मापदंडों के उल्लंघन से जुड़े सवाल का जवाब देने खड़े हुए। इस दौरान बैरवा मूल सवाल की जगह संभावित सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब पढ़ने लगे। इस पर भाजपा विधायक कल्पना देवी ने टोकते हुए कहा कि यह तो मैंने अभी पूछा ही नहीं। जिस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उपमुख्यमंत्री बैरवा को टोकते हुए कहा कि आप गलत जवाब पढ़ रहे है, जवाब यह नहीं है। डिप्टी सीएम ने तत्काल गलती मानते हुए माफी मांगी।

ग्रामीण अस्पतालों में नहीं है डॉक्टर-कम्पाउन्डर : मेहर

जयपुर (विसं)। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट बहस के दौरान कहा कि ''प्रदेश के ग्रामीण इलाके बेहाल हैं। अस्पतालों में डॉक्टर कंपांउडर नहीं हैं। जनता सोच रही है, डबल इंजन जा कहां रहा है, ले जा कहां रहा है? डबल इंजन की सरकार राजस्थान को गंगाजी ले जा रहा है।''

उन्होंने कहा कि बजट में न कोई कॉलेज और अस्पताल खोले हैं, न पानी- बिजली, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों पर ठोस काम किया है। एक विधायक को छह हैंडपंप और 3 ट्यूबबेल दिए हैं, ये वो कहां लगाएगा? विधानसभा क्षेत्र का इलाका बहुत बड़ा होता है, इतने से कैसे काम चलेगा? हमारी सरकार में हर विधायक को 100 हैंडपंप दिए जाते थे। इस सरकार में तो 6 हैंडपंप भी हमारे कहने से नहीं लगाए जाते। मेहर ने कहा कि बेवजह की घोषणाओं का मायाजाल गुमराह करने वाला है। पिछली बार टोडाभीम में बस स्टैंड की घोषणा की, वो आज तक नहीं बना। आपकी जेब में 100 रुपए है तो उतनी ही बात करो। लोगों को गुमराह करने के लिए 1000 रुपए की घोषणा मत करो।

मेहर ने कहा कि करौली के पहाड़ों पर 40 गांव बसे हैं, वहां आयरन की लीज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लोहा अयस्क निकालकर गुजरात ले जाएंगे। किसानों को जमीन से हटा रहे हैं और उद्योगपतियों के लिए ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हैं। राजस्थान में कोई स्टील कारखाना नहीं है। किसानों को उजाड़कर लोह अयस्क गुजरात जाएगा।

राज्य के प्रथम 'नेफैड बाजार' का उद्घाटन

'किसान से किचन तक' की संकल्पना पर आधारित है नेफैड बाजार : दक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन में नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नेफैड) द्वारा शुरु किये गए रिटेल आउटलेट 'नेफेड बाजार' का फीता काटकर उद्घाटन किया। 'किसान से किचन तक' की संकल्पना पर आधारित इस 'नेफेड बाजार' के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे।

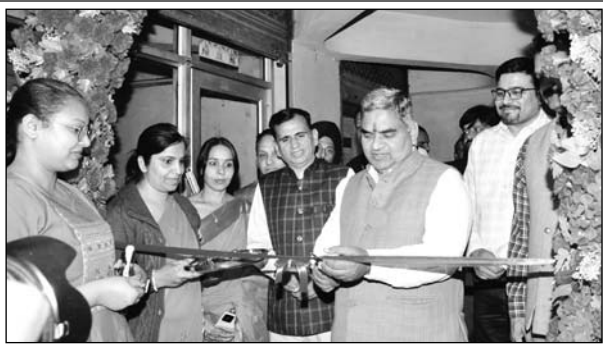

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने शुक्रवार को नेहरू सहकार भवन में रिटेल आउटलेट 'नेफेड बाजार' का उद्घाटन किया।

दक ने कहा कि राज्य के इस प्रथम 'नेफैड बाजार' का शुभारम्भ किसानों की समृद्धि एवं उपभोक्ताओं की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 1958 से किसानों की सहकारी संस्था के रूप में नेफेड किसानों को उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस प्रकार की पहलें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नेफेड बाजार न केवल उपभोक्ताओं को शुद्ध, प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएगा बल्कि किसानों के लिए स्थायी और लाभकारी विपणन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगा। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी 'नेफैड बाजार' स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां आनन्दी, नेफैड के निदेशक रामप्रकाश चौधरी सहित सहकारिता विभाग एवं नेफेड के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।